G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण

2022-2023

सार संक्षेपिका

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

महत्वपूर्ण बिन्दु

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की लघु संक्षेप पुस्तिका प्रदेश के प्रमुख सांख्यकीय आंकड़ों एवं प्रमुख उपलब्धियों का सार में लेख करती है।

आशा है कि यह जन-सामान्य व शासकीय तथा अशासकीय संस्थानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनांक 26-02-2023

अभिषेक सिंह

(अभिषेक सिंह, आई.ए.एस.)

आयुक्त

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

मुख्य बातें

आर्थिक अवलोकन, सार्वजनिक वित्त एवं बैंकिंग

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में मध्यप्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य तय किया है एवं प्रदेश इस ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिर कीमतों पर, इस वर्ष 2022-23 (अ.अ.) पर आधारित प्रदेश का GSDP 7.06% से बढ़ा है।
2. स्थिर कीमतों पर, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार रु. 65,023 हो गई, जो इस अवधि के दौरान 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.67% की वृद्धि हुई है।
3. मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार वर्ष 2001 में रु. 16,393 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में रु. 2,47,715 करोड़ हो चुका है। बजट में यह वृद्धि वर्ष 2001 की तुलना में लगभग 15 गुना है। प्रदेश का व्यय बजट विगत वर्ष में रु. 2,17,313 करोड़ (पू.अ.) 14% से बढ़कर रु. 2,47,715 (ब.अ.) करोड़ हुआ है।
4. राज्य ने राजकोषीय अनुशासन का निरंतर पालन किया है। ऋण-जीएसडीपी का अनुपात जो कि वर्ष 2005 में 39.5 प्रतिशत था, वह घटकर 2020 में 22.6 प्रतिशत हो गया। राज्य शासन का पूंजीगत व्यय रु. 37,089 करोड़ (पू.अ.) 23.18% से बढ़कर रु. 45,685 (ब.अ.) करोड़ हुआ है।
5. वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच, राज्य का अपना राजस्व 7.94 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी केवल 0.59 प्रतिशत बढ़ी । 2022-23 (BE) में, राज्य की अपनी राजस्व वृद्धि दर 13.32 प्रतिशत रही , जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 9.81 प्रतिशत बढ़ी। यह राजस्व प्राप्तियों में सुधार की शुरुआत को दर्शाता है, जिससे राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) का मार्ग प्रशस्त होता है।
6. सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए विगत दिसम्बर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन 'ई-कुबेर' के साथ एकीकरण को क्रियान्वित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में मध्य प्रदेश राज्य के समस्त 54 कोषालयों के

आहरण खाते खोले जा चुके हैं एवं सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं।

7. अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वर्ष 2005-06 से 2022-23 की अवधि में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण (Priority Sector Lending) का विस्तार 15.45 प्रतिशत CAGR की दर से हुआ है । इसका मान 9,437 करोड़ रुपए से बढ़कर रु. 2,15,427 करोड़ हो गया है । इसी क्रम में कृषि ऋण में 13.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एम.एस.एम.ई. में 30.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

8. राज्य में कुल अग्रिम (Advances) का 59.41 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया जो 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत लक्ष्य से अधिक है। जबकि कृषि को कुल ऋण का 32.2 प्रतिशत प्राप्त हुआ जो 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत लक्ष्य से अधिक है।

9. वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक कुल 3.85 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं।

10. डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत तीन जिलों बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया है।

11. मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूहों द्वारा अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है, उल्लेखनीय है की इसमे महिलाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2012-13 में 19,151 स्व सहायता समूह बने थे जिसमें 2,34,312 परिवार सम्मिलित थे, जो कि दिसंबर 2022 (वर्ष 2022-23) के अंत तक बढ़कर 4,20,838 हो गए हैं जिसमें 47,02,311 परिवार सम्मिलित हुए हैं । महिला स्व सहायता समूहों को दिसंबर 2022 तक आरएफ (Revolving Funds), सीआरएफ (Community Revolving Fund), सीसीएल (Cash Credit Limit), स्टार्टअप फंड के माध्यम से रु. 6178.26 करोड़ का कुल वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है ।

कृषि, खाद्य प्रबंधन, एवं प्राकृतिक संसाधन

1. राज्य ने 2013-14 में 174.8 लाख टन की तुलना में 2022-23 (अग्रिम अनुमान) में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसी तरह इस अवधि में धान का उत्पादन 53.2 लाख से बढ़कर 131.8 लाख टन हो गया है।
2. वर्ष 2020-21 की तुलना में, वर्ष 2021-22 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
3. वर्ष 2020-21 की तुलना में कुल फसलों के उत्पादन में वर्ष 2021-22 में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।
4. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को 'मिलेट वर्ष' घोषित किया है। भारत सरकार द्वारा इसे श्री अन्न कहा गया है । मध्यप्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, एवं श्री अन्न के उत्पादन और निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020 में 'एमपी राज्य मिलेट मिशन' और 'मुख्यमंत्री कोदो-कुटकी खेती सहायता योजना' प्रारंभ की है।
5. कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2021-22 में, 90 लाख से अधिक किसानों की फसलों का बीमा किया गया ।
6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) तकनीक पर आधारित ई_गिरदावरी परियोजना के माध्यम से गिरदावरी संचालन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। इसी क्रम में, पीएम किसान के अंतर्गत 85 लाख में से 76 लाख लाभार्थियों की खसरा जानकारी दर्ज की गयी है।
7. सिंचाई सुविधा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता में 585 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर (वर्ष 2003) से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक (वर्ष 2022 में) हो गई है, और इसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।
8. मध्यप्रदेश द्वारा व्यापक हितग्राहकों के साथ विस्तृत परामर्श के माध्यम से राज्य जल नीति, 2022 का प्रारूप तैयार किया गया है। नई नीति में जल संसाधन संरक्षण और सुरक्षा के लिए पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
9. रामसर आर्द्र क्षेत्रों (Wetlands) का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। मध्य प्रदेश की तीन आर्द्रभूमि (इंदौर में सिरपुर आर्द्रभूमि तथा यशवंत सागर, और शिवपुरी जिले में

सख्य सागर) को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र क्षेत्र सम्मेलन (रामसर सम्मेलन) द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया है।

10. मध्यप्रदेश में मत्स्योत्पादन में वर्ष 2015 से 2022 की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 15.39 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है ।

11. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश हीरा, ताम्र अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय, तथा कोयला के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है ।

उद्योग, व्यापार, अधोसंरचना, एवं कनेक्टिविटी

1. $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों और निर्यातक हितों के बीच सेतु बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (मध्यप्रदेश ट्रैड प्रमोशन कॉउन्सिल) की स्थापना की गयी है।
2. मध्य प्रदेश में स्वरोजगार, नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का वर्ष 2022 में क्रियान्वित किया गया है ।
3. मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश (एफ डी आई) निरंतर बढ़ रहा है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में राज्य को रु. 1560 करोड़ (यूएस $ 208 मिलियन) का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ।
4. एक्स्पोर्ट प्रीपेर्डनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लैंड-लॉक्ड राज्यों (हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और म.प्र.) में मध्य प्रदेश ने निर्यात मूल्य के मामले में राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है और अब हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर है ।
5. मध्यप्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017 से 2022 के मध्य 8.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वर्ष 2021-22 में निर्यात रु. 58,407 करोड़ तक पहुंच गया।
6. मध्यप्रदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व को समझते हुए अनेकों योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में चयनित पर्यटन संबंधित सर्किटों को एंड टू एंड समर्थन दिया जा रहा है। पर्यटन के पूर्ण पैकेज के रूप में 50 स्थलों का चयन किया गया है। वर्ष 2004-05 में पर्यटन का बजट आवंटन रु. 11.2 करोड़ से लगभग 21 गुना बढ़ते हुए वर्ष 2022-23 में रु. 244.6 करोड़ तक पहुँच गया है ।
7. मध्यप्रदेश में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में धार्मिक पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में 122% की वृद्धि हुई है और 2022 में अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में 58% की वृद्धि हुई है।
8. मध्यप्रदेश की विद्युत क्षमता वर्ष 2003 में 5173 मेगावाट से लगभग 5 गुना से अधिक बढ़ते हुए वर्ष 2022 में 28000 मेगावाट से अधिक हो गई है। विगत एक दशक में ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में लगभग 207

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता वर्ष 2012 में 570.2 KWH से बढ़कर वर्ष 2022 में 1184.9 KWH हो गई है।

9. प्रदेश में 2003 से लेकर 2022 तक सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन 44,000 किलोमीटर से बढ़कर 4,00,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है।

10. ग्वालियर-झांसी (एनएच 75), मनगवां (रीवा)-यूपी बॉर्डर (एनएच 27), सिवनी-महाराष्ट्र बॉर्डर (एनएच 7) आदि को बेहतर बाजार पहुंच और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए विकसित किए गए हैं।

11. भविष्य के शहरी आवागमन के मुख्य स्रोत के रूप में जानी जाने वाली मेट्रो रेल का कार्य भोपाल और इंदौर में प्रगति पर है , इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 14,000 करोड़ है।

12. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए दूरगामी लक्ष्य तय किए गये हैं। अक्षय ऊर्जा राज्य की अनेक प्रतिबद्धताएं में से एक हैं। वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत अक्षय एवं हरित ऊर्जा से प्राप्त हो इसके लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, बिजली व्यापार बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है ।

13. ओंकारेश्वर में रु. 3 हज़ार 50 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2027 तक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 20 हज़ार मेगावाट करने का लक्ष्य है।

14. मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 का लॉन्च की गया है। मध्यप्रदेश की यह अभिनव नीति है जिसमें राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।

15. मध्यप्रदेश में कुल 601 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं इनमें से 145 मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में स्थित हैं।

समावेशी सामाजिक विकास

1. मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन स्वरूप एवं अन्य प्रयासों के कारण जो जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 (NFHS-4) (2015-2016) में 927 था, वह NFHS-5 (2019-2021) में बढ़कर 956 हो गया है |
2. इसी क्रम में NFHS-3 (2005-2006) में साक्षर महिलाओं का अनुपात 44.4 था जो NFHS-5 (2019-2021) में 65.4 हो चुका है |
3. मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 में सम्पन्न पंचायत आम निर्वाचन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से लगभग 17,000 महिलायें चुनाव जीती है| इनमें से 14,378 पंच,1907 सरपंच, 429 उप-सरपंच, 381 जनपद सदस्य एवं 46 जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है जो महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण एवं सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
4. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है, अनुसूचित जनजाति उप योजना का 2004-05 में कुल बजट आवंटन रु. 1,662.01 करोड़ था जो 2022-23 (ब.अ.) में बढ़कर रु. 26,940.68 करोड़ हो गया है, इस प्रकार इस मद में लगभग 1620 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
5. मध्य प्रदेश द्वारा 15 नवंबर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा (PESA) नियमों को अधिसूचित किया गया है। जल, जंगल, जमीन, श्रम, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय परंपराओं के सुदृढ़ीकरण के अधिकार प्राप्त हुए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य

1. मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को उत्कृष्टता के स्तर तक लाने हेतु एवं समस्त आधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करने की दृष्टि से सी.एम. राईज (CM RISE) योजनांतर्गत प्रथम चरण में विभाग के 370 स्कूलों का सी.एम.राईज स्कूलों के रूप में संचालन प्रारंभ किया गया है।
2. मध्यप्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की स्कूलों तक पहुँच बढ़ाने के लिए सायकल वितरण किया जाता है , वर्ष 2022-23 में कक्षा 6 से 9 में पढ़ने वाले लगभग 1 लाख छात्रों को सायकल वितरण किया गया है । यह शासकीय स्कूल से 2 कि.मी. दूर बसाहट में रहने वाले छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मददगार होगा।
3. बालिका शिक्षा मध्यप्रदेश की प्राथमिकताओं में से एक है । प्रदेश में 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय और अतिरिक्त 324 कन्या छात्रावास स्थापित किए गए है, इन छात्रावासों से 56 हजार बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।
4. गाँव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है । इस योजना में चयनित छात्रा को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रु 500/- प्रति माह (अधिकतम 10 महीने के लिए) भुगतान किया जाता है । 2022-23 में कुल 23,269 छात्राओं को योजना का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार प्रतिभा किरण योजना ने शहरी छात्राओं को योजना का लाभ दिया गया है
5. मध्यप्रदेश में कुल 10.88 हजार (97.66% उपलब्धि) हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र संचालित हैं। इन हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों के अतिरिक्त आयुष विभाग द्वारा भी 562 आयुष-हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
6. राज्य शासन द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुपोषण में कमी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में प्रभावी रणनीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में राज्य शासन की सहायता कर रही है।
7. NFHS-3 (2005-2006) सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश में '5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण' 12.6% था, जो कम हो कर NFHS-5 (2019-2021) सर्वे में 6.5% हो चुका है|
8. NFHS-3 (2005-2006) अनुसार, संस्थागत प्रसव 26% था जो NFHS-5

(2019-2021) में 90.7% हो गया है |

9. मध्यप्रदेश में बाल मृत्यु दर (IMR) NFHS-3 (वर्ष 2005-2006) में 70 थी जो घट कर NFHS-5 (वर्ष 2019-2021) में 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है।

10. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (SRS) के अनुसार वर्ष 2004-2006 में मध्यप्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 335 था , जो वर्ष 2018-2020 (SRS बुलेटिन नवंबर 2022) में घट कर 173 हो गया है।

11. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत PPP मॉडल के माध्यम से प्रदेश में निम्न बेस्ट प्रैक्टिस संचालित की जा रही है-

- निशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना (वेट लीज मॉडल) के अंतर्गत समस्त 51 जिला अस्पतालों एवं चिन्हांकित सिविल अस्पतालों में 134 प्रकार की जांच की सुविधा मरीजों को प्रदाय की जा रही है, अब तक 45.42 लाख हितग्राहियों की 1 करोड़ 65 लाख जाँचें की जा चुकी हैं। मरीजों को जांच रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में तथा मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध करायीं जा रही हैं।
- हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 324 हब (CHC-251, CH-49, PHC-14, UPHC-10) के माध्यम से 1492 स्पोक (PHC-1209, UPHC-200, CHC-66, CH-17) मे कुल 45 प्रकार की निःशुल्क जांच की जा रही है। 16.13 लाख हितग्राहियों की 64.90 लाख जाँचें की जा चुकी हैं।
- डायलीसिस सेवा योजनान्तर्गत प्रत्येक जिला चिकित्सालय की इकाई में न्यूनतम 5 डायलिसिस मशीन व उप जिला स्तरीय चिकित्सालय में 3 मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। आज दिनांक तक 7063 रोगी पंजीकृत किये गये व 4 लाख 58 हजार से अधिक डायलिसिस किये गये। वर्तमान में इन इकाइयों में 1276 रोगियों को सेवायें दी जा रही हैं तथा प्रति माह 9 हजार डायलिसिस किये जा रहे हैं।
- सीटी स्कैन सुविधा के अंतर्गत 50 जिला चिकित्सालयों एवं 4 सिविल अस्पतालों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों एवं आयुष्मान कार्डधारी रोगियों को निःशुल्क सीटी स्कैन सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक 2.51 लाख से अधिक सी टी स्कैन किए जा चुके हैं।
- कैंसर की देखभाल हेतु वर्तमान में मध्यप्रदेश के 51 जिलों में प्री-कैंसर के उपचार हेतु थर्मल अबलेशन डिवाईस के साथ डे-केयर कैंसर कीमोथैरैपी यूनिट स्थापित है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड कैंसर केयर मॉडल अंतर्गत डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी सेवाओं का विस्तारण चिन्हित उच्च ओपीडी लोड वाले

सिविल अस्पतालों में भी किया गया हैं। इसके अतिरिक्त सरवाईकल प्री-कैंसर के उपचार हेतु थर्मल अबलेशन डिवाईस की उपलब्धता चिन्हित सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुनिश्चित की गई है।

- एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली कि नवीन व्यवस्था के अंतर्गत उन्नत तकनीकी कि सहायता से एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 2052 एम्बुलेंस संचालित है, और तीन प्रकार के वाहन सम्मिलित है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एवं जननी एक्स्प्रेस।

सुशासन एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

1. जन सामान्य की समस्याओं एवं शासन से जुड़ी गतिविधियों के सुगम एवं पारदर्शी संचालन के उद्देश्य अनेकों प्रयास किए गए हैं। ई गवर्नन्स के माध्यम से जन जन तक सेवाओं और सुविधाओं की पहुँच बढ़ाई गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समाधान ऑनलाइन, समाधान एकदिवस, प्रगति, साईबर तहसील, MLA डैशबोर्ड, जनसुनवाई, मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की स्थापना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री जन सेवा योजना, मुख्यमंत्री डैश बोर्ड, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम इत्यादि इस दिशा में प्रमुख प्रयास हैं।
2. सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 है, इस हेल्पलाइन के द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी 2023 की अवधि में 2 करोड़ पाँच लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई जिनमे से 98.8 प्रतिशत का निवारण कर दिया गया है।
3. मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है । अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है।
4. मध्य प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2012 में राज्य मिशन मोड परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी 2.0) के तहत जिला/ उप-जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए की गई। जनवरी 2023 तक, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं।
5. सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन: मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (MPSeDC) ने कर्मचारियों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और सभी शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण समन्वय इकाई (TCU) की स्थापना की है। राज्य के 51 जिलों में ई-दक्ष केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनवरी, 2023 तक मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों के लगभग 5.8 लाख कर्मचारी ई-दक्ष केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं।
6. साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एवं डेटा की गुणवत्ता और सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है।
7. प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की संख्या में वृद्धि हुई है, जो राज्य में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की प्रगति की ओर संकेत कर रही है। 2003-04

में राज्य में यूएलबी की कुल संख्या 337 थी जो अब बढ़कर 413 हो गई है।

8. इंदौर नगर निगम पिछले 6 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार ओडीएफ+ और वाटर++ नगर होने के साथ यह देश का एकमात्र 7-स्टार रेटेड नगर है।

9. पीएम स्वनिधि के प्रथम चरण (रु. 10,000 ऋण राशि) के तहत् राज्य देश में पहले स्थान पर है जिसने रु. 521.66 करोड़ का ऋण 5.25 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडरों को वितरित किया है।

a. पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण (रु. 20,000 की ऋण राशि) के तहत् मध्यप्रदेश 1,30,857 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को रु. 255.79 करोड़ का ऋण वितरित करके देश में दूसरे स्थान पर है।

b. पीएम स्वनिधि योजना के तीसरे चरण (रु. 50,000 की ऋण राशि) के तहत् मध्यप्रदेश 6182 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को रु. 30.9 करोड़ का ऋण वितरित करके देश में तीसरे स्थान पर है।

10. भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का पुनर्विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया गया है। इस परियोजना पर कुल रु. 500 करोड़ का निवेश किया गया है। यह स्टेशन, भारत में का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है।

11. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजार्थिक विकास के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में पौराणिक धरोहर एवं जनजातीय गौरव को महत्व देते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है :-

- श्री महाकालेश्वर धाम, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है। इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि एक लाख लोग लगभग एक घंटे के समय में श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। यह व्यवस्था, धार्मिक स्थलों पर अधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्था के कारण इन धर्मस्थलों और इनकी अनुपम धरोहर से दूर होती जा रही पीढ़ी को पुनः इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ने का कार्य करेगी। महाकाल माहालोक का निर्माण 11 अक्तूबर 2022 को हुआ, जिसके पश्चात कुछ ही समय की अवधि में पर्यटकों की संख्या में 2021 के मुकाबले लगभग 18 गुना की वृद्धि हुई है।
- ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहु धातु की भव्य प्रतिमा एवं अद्वैत धाम, अद्वैत वन, अद्वैत धाम, अद्वैत वेदांत संग्रहालय एवं संस्थान का निर्माण कार्य लगभग रु. 2200 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

- क्रांतिवीर टंट्या भील की बलिदान भूमि पातालपानी में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नवतीर्थ स्थल बनाया जा रहा है , यहाँ एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।
- भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना' प्रारंभ की गई है जिसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिये एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएंगी।

---------0----------

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004
फोन : 0755-2551395
वेबसाइट : http://des.mp.gov.in, ई-मेल : des@mp.gov.in